

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/ 9187

जयपुर, दिनांक 24-9-24

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : Custody, retention, inspection, supply and disposal of election records relating to general/bye election to the House of the People and State Legislative Assembly-regarding

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 4/2024/SDR/Vol.II दिनांक 06.09.2024

संदर्भ :

Sl. No.	Letter No.	Dated
1.	No. 4/2008/SDR	29.01.2009
2.	No. 3/ER/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2016	07.09.2016
3.	No. 464/INST/2022/EPS	19.06.2023
4.	No. 464/Counting Arrangements /2023-EPS	18.07.2023
5.	No. 464/Strong room/2023-EPS	18.07.2023
6.	3/ER/2023/SDR/Vol.V	27.02.2024
7.	3/ER/2023/SDR/Vol.IV	06.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92-94 में लोक सभा और राज्य विधान सभा के आम/उपचुनाव के संबंध में निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, प्रतिधारण, निरीक्षण, आपूर्ति और निपटान के प्रावधान हैं। नियम 92 में मतपेटियों और निर्वाचन से संबंधित कागजात की अभिरक्षा की बात कही गई है, नियम 93 में निर्वाचन पत्रों के उत्पादन और निरीक्षण की बात कही गई है; जबकि उनके प्रतिधारण और निपटान के प्रावधान उक्त नियमों के नियम 94 में निहित हैं।

2. ऊपर बताए गए नियमों के अलावा, आयोग ने समय-समय पर चुनाव पत्रों की अभिरक्षा, भंडारण, निरीक्षण, आपूर्ति, प्रतिधारण और निपटान के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, नामांकन, जांच और उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीकों के आवंटन, ईवीएम की तैयारी, प्रचार गतिविधियों, मतदान, मतगणना और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया के दौरान कई रिकॉर्डिंग उपकरणों (जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, वेबकास्टिंग) के माध्यम से चुनाव

प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की रिकॉर्डिंग के लिए आयोग के निर्देश हैं। इन रिकॉर्डिंग को आयोग के निर्देशों और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में सीडी/भंडारण उपकरणों में संग्रहीत किया जाना है।

3. नियम 92 के तहत जब कोई विधानसभा या संसदीय क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हो, तो उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव संबंधी कागजात निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले ऐसे किसी एक जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे, जिसे चुनाव आयोग निर्देश दे। इस व्यवस्था के तहत, आम तौर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो खुद ऐसे बहु-जिला निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी है या ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी जो उसके जिले के अधिकार क्षेत्र में काम करता है, इन कागजातों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। एक से अधिक जिलों में फैले विधानसभा क्षेत्र के मामले में, चुनाव रिकॉर्ड उस जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे, जिसे उस विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी रिपोर्ट करता है।

4. यद्यपि चुनावी कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनावी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरणों को तैनात करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, तथापि, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता उपायों को बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न हितधारकों की समावेशिता को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया, आयोग ने मौजूदा कानून और नियमों को पूरक और मजबूत करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक क्रियाविधि पेश की हैं और ऐसे कदम विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान प्रतिबंधात्मक हैं, हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित रिकॉर्ड निर्देशात्मक व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को उदारतापूर्वक प्रदान किए जाते हैं। हालांकि, हाल के समय के अनुभवों से पता चलता है कि आयोग के निर्देशों/अनुदेशों में ऐसे उदार प्रावधानों का दुरुपयोग कुछ गैर-प्रतियोगियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और सोशल मीडिया पर बदनामी अभियान के माध्यम से चुनावी प्रक्रियाओं पर गलत धारणा का प्रचार करने के लिए किया गया है। इसलिए, आयोग चुनाव पत्रों और उपर्युक्त घटनाओं की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की अभिरक्षा, प्रतिधारण, निरीक्षण, आपूर्ति और निपटान से संबंधित पहले के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, इस संदर्भ में निम्नलिखित व्यापक और समग्र निर्देश जारी करता है:

A. Pre Nomination period -

i) चुनाव की घोषणा और अधिसूचना के बीच की अवधि से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और अन्य दस्तावेज, परिणाम की घोषणा तक रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। इसके बाद इन अभिलेखों को सील करके जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा/रख लिया जाएगा, जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार इन अभिलेखों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

ii) परिणाम की घोषणा के बाद, इन अभिलेखों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94 (सी) के अनुसार तीन महीने की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। इन अभिलेखों का निपटान पैरा 7 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

iii) जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान, वैधानिक दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए खोला जाएगा तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार(ओं) या मतदाता(ओं) द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन अभिलेखों के निरीक्षण तथा आपूर्ति के लिए निर्देश पैरा 6 में दिए गए हैं।

B. Nomination process-

i) फोटोग्राफी, सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्ज किए गए चुनाव पत्र और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को परिणाम की घोषणा तक रिटर्निंग ऑफिसर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके बाद इन अभिलेखों को सील करके जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार इन अभिलेखों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।

ii) परिणाम की घोषणा के बाद, इन अभिलेखों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94 (सी) के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। इन अभिलेखों का निपटान पैरा 7 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

iii) जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान, वैधानिक दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए खोला जाएगा तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार(ओं) या मतदाता(ओं) द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन अभिलेखों के निरीक्षण तथा आपूर्ति के लिए निर्देश पैरा 6 में दिए गए हैं।

C. Campaign period-

i) जहां तक चुनाव व्यय निगरानी टीमों, उड़न दस्तों, एसएसटी आदि द्वारा बनाए गए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार गतिविधियों के दस्तावेजों, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी का संबंध है, परिणाम घोषित होने तक रिकॉर्ड रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके बाद, इन अभिलेखों को सील कर दिया जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार इन अभिलेखों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।

ii) परिणाम की घोषणा के बाद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94 (सी) के अनुसार इन रिकॉर्ड्स को छह महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा। इन रिकॉर्ड्स को पैरा 7 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया जा सकता है।

iii) जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान, इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिए खोला जाएगा तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी या मतदाता की मांग पर ही उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन अभिलेखों के निरीक्षण तथा आपूर्ति के लिए निर्देश पैरा 6 में दिए गए हैं।

D. Inside and outside the polling station:

- i) मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर निर्धारित प्रारूप में दर्ज की गई मतदान कार्यवाही, मतदान मशीनें और फोटोग्राफी/वेबकास्टिंग/सीसीटीवी/वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज की गई घटना को परिणाम घोषित होने तक रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके बाद, इन अभिलेखों को सील कर दिया जाएगा और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा/रख लिया जाएगा।
- ii) ऐसे अभिलेखों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) में उल्लिखित अभिलेख माना जाएगा तथा उन्हें खोला नहीं जाएगा तथा उनकी विषय-वस्तु का निरीक्षण किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालांकि, मतदान केंद्रों के अंदर वेबकास्टिंग डेटा और वीडियोग्राफी डेटा/फोटोग्राफी को जांच प्रक्रिया के दौरान उपयोग के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा, यदि आवश्यक हो।
- iii) इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस के तहत, पीठासीन अधिकारी को केवल फॉर्म 17सी भाग I में उनके द्वारा तैयार किए गए दर्ज किए गए वोटों के खाते की एक सत्य प्रमाणित प्रति उपस्थित प्रत्येक मतदान एजेंट को, उक्त मतदान एजेंटों से रसीद प्राप्त करने के बाद, केवल मतदान समाप्ति पर प्रस्तुत करनी होगी और कोई अन्य दस्तावेज नहीं देना होगा।
- iv) परिणाम की घोषणा के बाद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94 (बी) के अनुसार इन रिकॉर्ड्स को एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। इन रिकॉर्ड्स को पैरा 7 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया जा सकता है।
- v) सक्षम न्यायालय के आदेश पर, यदि ऐसे डेटा/रिकॉर्ड की प्रतियां उस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार या निर्वाचकों को प्रदान की जानी हैं, तो उन्हें पैरा 6 में दिए गए मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

E. Counting and declaration of result:

- i) मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी/सीसीटीवी के माध्यम से दर्ज की गई मतगणना और परिणाम की घोषणा की कार्यवाही को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधिवत सील कर दिया जाएगा और उसे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।
- ii) ऐसे अभिलेख निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) में उल्लिखित अभिलेखों का हिस्सा हैं और इन्हें खोला नहीं जाएगा तथा इनकी विषय-वस्तु का निरीक्षण किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

iii) परिणाम की घोषणा के बाद, इन अभिलेखों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94(बी) के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। इन अभिलेखों का निपटान पैरा 7 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

iv) सक्षम न्यायालय के आदेश पर, यदि ऐसे डेटा/रिकार्ड की प्रतियां उस निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी(यों) या मतदाता(यों) को उपलब्ध कराई जानी हैं, तो उन्हें पैरा 6 में दिए गए मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

v) हालांकि, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93(3) के प्रावधान के अनुसार, नियम 64 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी गई रिटर्न की प्रतियां जैसे रिटर्न फॉर्म 21-ई, फॉर्म 21सी या फॉर्म 21डी और फॉर्म 20 में चुनाव परिणाम पत्रक तैयार किये जाते हैं। प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपये का शुल्क अदा करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

vi) इसके अलावा, फॉर्म 17सी भाग II मतगणना का परिणाम है और इसे मतगणना के समय तैयार किया जाता है। इस पर मतगणना पर्यवेक्षक और उम्मीदवार या उनके चुनाव/मतगणना एजेंट भी हस्ताक्षर करते हैं। फॉर्म 17सी भाग II की एक प्रति मतगणना के समय चुनाव/मतगणना एजेंट को दी जाती है।

F. EVM preparations:

i) ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी के दौरान कार्यवाही निर्धारित प्रारूप में और फोटोग्राफी/सीसीटीवी/वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज की गई। चुनाव याचिका दाखिल करने की अवधि तक एफएलसी, रैंडमाइजेशन, कमीशनिंग, फैलाव, भंडारण और अन्य गतिविधियां, तैयारियों के विभिन्न चरणों में गोदामों या स्ट्रॉन्ग रूम में परिणाम की घोषणा तक रिटर्निंग ऑफिसर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी। इसके बाद, इन अभिलेखों को सील कर दिया जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार इन अभिलेखों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।

ii) ऐसे अभिलेख निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93 के उप-नियम (1) और (1A) में उल्लिखित अभिलेखों का हिरसा हैं और उन्हें खोला नहीं जाएगा और उनकी सामग्री का निरीक्षण नहीं किया जाएगा या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अलावा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि कोई हो, तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग से रखा जाएगा और उसे ऊपर उल्लिखित अनिवार्य रिकॉर्डिंग के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

iii) परिणाम की घोषणा के बाद, इन अभिलेखों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94 (बी) के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। इन अभिलेखों का निपटान पैरा 7 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

iv) सक्षम न्यायालय के आदेश पर, यदि ऐसे डेटा/रिकार्ड की प्रतियां उस निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी(यों) या मतदाता(यों) को उपलब्ध कराई जानी हैं, तो उन्हें पैरा 6 में दिए गए मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

G. Other Records:

i) किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखा का समस्त रिकार्ड, जिसने उसे समय और ढंग से दाखिल कर दिया हो, एक वर्ष की अवधि तक या आयोग के समक्ष मामला लंबित रहने तक सुरक्षित रखा जाएगा।

ii) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 ए के तहत अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार के चुनाव खर्च के खाते से संबंधित सभी रिकॉर्ड, उप-नियम के तहत आयोग के निर्णय की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखे जाएंगे। निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 की धारा (8) के अनुसार, यदि आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अयोग्यता हटा दी गई है, तो ऐसे हटाए जाने के एक वर्ष बाद अभिलेख नष्ट कर दिए जाएंगे।

iii) चुनौती दिए गए मतों की सूची (प्रपत्र 14), चुनौती शुल्क के संग्रह के लिए प्रयुक्त रसीद बुक को एक वर्ष तक या जब तक उनका ऑडिट नहीं हो जाता और ऑडिट आपत्तियों (यदि कोई हो) का निपटारा नहीं हो जाता, जो भी बाद में हो, तक सुरक्षित रखा जाएगा।

iv) डाक मतपत्रों का प्रेषण रजिस्टर, सुरक्षा जमा का रजिस्टर, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की नियुक्ति के आदेश परिणामों की घोषणा के छह महीने बाद तक बनाए रखे जाएंगे।

v) जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान, इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिए खोला जाएगा तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी या निर्वाचक को मांगे जाने पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन अभिलेखों के निरीक्षण तथा आपूर्ति के लिए अनुदेश पैरा 6 में दिए गए हैं।

vi) इन अभिलेखों का निपटान ऊपर उल्लिखित अवधारण अवधि की समाप्ति के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया जाएगा।

5. गैर-चुनाव अवधि के दौरान तैयार किए गए मतदाता सूची की तैयारी और अद्यतन से संबंधित अभिलेखों के अलावा अन्य अभिलेख भी हैं, जो चुनाव-पूर्व अवधि के दौरान सामान्य चुनावी प्रबंधन से संबंधित हैं। ऐसे अभिलेखों की आवश्यकता संदर्भ, आंतरिक लेखा परीक्षा और स्टॉक लेने आदि जैसे आंतरिक उपयोग के लिए हो सकती है और ये जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में होंगे। इन अभिलेखों तक पहुँच केवल आधिकारिक उद्देश्य तक ही सीमित होगी और किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इन अभिलेखों को उस चक्र के पूरा होने के 30 दिन बाद या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय किए गए समय के अनुसार जो भी बाद में हो, नष्ट कर दिया जाएगा।

6. Inspection and supply of election papers and electronic contents given in Para A to G and fee thereof

(i) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93 के प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित आयोग के निर्देशों के अधीन, पात्र चुनाव दस्तावेजों का निरीक्षण और आपूर्ति चुनाव के परिणाम की घोषणा के 45 दिन पूरे होने के बाद ही प्रदान की जाएगी।

(ii) यदि कोई चुनाव याचिका है या कोई अन्य याचिका किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर या लंबित है, तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद ही दस्तावेजों का निरीक्षण और आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

(iii) किसी भी पात्र वैधानिक चुनाव रिकॉर्ड के निरीक्षण और प्रति की आपूर्ति की अनुमति केवल उम्मीदवार या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक द्वारा चुनाव रिकॉर्ड से संबंधित विवरण वाले लिखित आवेदन पर ही दी जाएगी।

(iv) आवेदन में स्पष्ट रूप से खुलासा होना चाहिए कि आवेदक का ऐसे दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और ठोस हित है और ऐसे हित की प्रकृति है।

(v) जब आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी दस्तावेज का निरीक्षण या प्रमाणित प्रति आवश्यक हो तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(vi) किसी भी चुनाव रिकॉर्ड को हटाने या क्षति पहुंचाने या विकृत करने से बचने के लिए, अधिकारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक है और यदि अनुरोध किया गया है तो एक साथी के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) चुनाव व्यय के खाते के मामले में, निरीक्षण और उसकी प्रतियों की आपूर्ति निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 88 और इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर-2023 की हैंडबुक के अध्याय 18 में उल्लिखित आयोग के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(viii) इसके लिए आवेदन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो राजस्व अधिकारी द्वारा निपटाए गए मामले के संबंध में किए गए समान आवेदन के लिए अपनाई जाती है।

(ix) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2) के अंतर्गत, आयोग संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी या निर्वाचक द्वारा आवेदन करने पर निर्वाचन अभिलेखों के निरीक्षण तथा प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित शुल्क निर्धारित करता है:

Sl.no.	Applicant	Type of Election document/record	Fee for supply of certified copy and timeline	Fee for inspection and timeline
1.	Candidate of the constituency concerned	Any eligible statutory document other than the documents covered under Rule 93(1) of CE Rules 1961. And	Nil. within 30 days of receiving of written application or as per the order of the competent court.	Inspection shall be allowed on the day following the date on which the application is made or on a subsequent day on payment of fee of Rs. 5 per hour of inspection or part thereof.
2.	any elector of the constituency concerned	In case of election records covered under Rule 93(1) of CE Rules 1961 and non-statutory documents/records, order of the competent court is required.	Rs.300/- per CD/storage device (excluding cost of CD/storage device), and @ Rs.2/- per page in case of documents. within 30 days of receiving of written application or as per the order of the competent court.	Inspection on an urgent application shall be allowed on the same day in that case the fees shall be Rs. 10 per hour of inspection or part thereof.

7. Disposal of election papers and electronic contents-

(i) चुनाव पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का निपटान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसे चुनाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उपर्युक्त निर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा।

(ii) इन अभिलेखों के निपटान से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या कोई चुनाव याचिका या कोई अन्य याचिका किसी राक्षम न्यायालय में दायर या लंबित है।

(iii) यदि चुनाव के लिए कोई चुनाव याचिका दायर/लंबित नहीं है, तो उपर्युक्त चुनाव अभिलेखों को उपर्युक्त अवधारण अवधि की समाप्ति के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से नष्ट किया जा सकता है।

(iv) जहां कोई चुनाव याचिका या कोई अन्य याचिका न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित है, वहां उससे संबंधित अभिलेखों को तब तक नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी याचिका के अंतिम रूप से निपटान की तारीख से तीन माह की अवधि समाप्त न हो जाए।

(v) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभिलेखों का निपटान करने से पहले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और संबंधित राजनीतिक दलों को लिखित सूचना दे दी जाएगी।

(vi) अंतिम परिणाम पत्रक (फॉर्म 20), चुनाव के परिणाम की घोषणा (फॉर्म 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 23 और 23A) और चुनाव रिटर्न (फॉर्म 21 E और 23 B) को चुनाव के स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए।

(vii) एक निश्चित समयसीमा में नष्ट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की तालिका अनुलग्नक 'A' और 'B' में देखी जा सकती है।

8. (क) एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) के अर्थ में "सक्षम न्यायालय" से तात्पर्य या तो ऐसा न्यायालय है जिसे चुनावी अपराधों आदि पर विचारण करने का अधिकार है, जिसके अभियोजन के लिए उक्त नियम में उल्लिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं या वह न्यायालय है जिसे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80ए के अंतर्गत चुनाव याचिका पर विचारण करने का अधिकार है।

(ख) यदि कोई चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और साथ ही चुनाव संबंधी अभिलेख भी चुनावी अपराध के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी उस चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय से अनुमति लेगा, इससे पहले कि अभिलेख उस न्यायालय को मांगे जाने पर/याचिकाकर्ता को अनुरोध पर उपलब्ध कराए जाएं।

9. फोटोग्राफी/वेबकास्टिंग/सीसीटीवी/वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज की गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के संबंध में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि unedited recordings को उचित स्टोरेज डिवाइस में संग्रहीत किया जाना चाहिए और सील किया जाना चाहिए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के उस विशेष चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद तिथि, समय, समय अवधि, स्थान का नाम, निर्वाचन क्षेत्र और चुनाव सहित राज्य/जिला/एसी/रिकॉर्डिंग की तारीख/स्थान/रिकॉर्ड की गई घटना का सार, सभी विवरण स्पष्ट रूप से लेबल किए गए हों। सीडी/स्टोरेज डिवाइस को निम्नलिखित मानक फॉर्मूलेशन में एक समान कोड नंबर के साथ अनुक्रमित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभिन्न प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग विधिवत सूचीबद्ध की गई हो तथा उचित लॉकिंग सील के साथ उसे बरकरार और असंपादित रखा जाए ताकि सील किए जाने के बाद कोई भी उसकी प्रतिलिपि न बना सके। किसी भी परिस्थिति में सीडी/भंडारण उपकरणों की सामग्री की प्रामाणिकता और सत्यता की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी तथा इन्हें 'जैसा है' के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग प्रदान करते समय रिकॉर्डिंग के विवरण जैसे चुनाव, स्थान, घटना तिथि और समय आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग जो चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) के तहत निर्दिष्ट चुनाव पत्रों का हिस्सा हैं, उन्हें चुनाव पत्र स्ट्रांग रूम में ट्रंक में संग्रहीत किया जाएगा, जो ईवीएम/वीवीपैट स्ट्रांग रूम से भिन्न दस्तावेजों के लिए निर्दिष्ट है, जहां उस चुनाव से संबंधित सभी वैधानिक दस्तावेज संग्रहीत किए गए हैं। संदर्भ 3 उद्धृत और रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक, 2023 के पैरा 19.8 के अनुसार जारी किए गए अभिलेखों के निरीक्षण पर अन्य प्रशासनिक निर्देशों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

10. Protocol for safe storage of Polled EVMs, VVPAT, VVPAT slips and election papers:-

ईवीएम और वीवीपैट मैनुअल के नवीनतम संस्करण में निहित सभी मौजूदा निर्देशों और उद्धृत संदर्भ 5 में मतदान किए गए ईवीएम, वीवीपैट, वीवीपैट पर्चियों और चुनाव पत्रों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में आयोग के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा।

11. Protocol for opening of election papers strong room for supply of copies/recordings:

एक अलग लॉग बुक भी रखी जाएगी और स्ट्रांग रूम के खुलने की स्थिति में, दिनांक, समय, अवधि और व्यक्ति(ओं) के नाम, स्ट्रांग रूम खोलने के उद्देश्य के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। स्ट्रांग रूम खोलने के लिए अन्य प्रोटोकॉल जैसे कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पूर्व सूचना देना, स्ट्रांग रूम में गतिविधि की वीडियोग्राफी, जिसमें खोलना और फिर से सील करना आदि शामिल है, का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

12. चुनाव संबंधी कागजात और दस्तावेजों को जिला या राज्य में केंद्रीय रूप से नष्ट किया जाएगा, जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तय करेंगे। विभिन्न चुनावी डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सीडी, डीवीडी, पेनड्राइव, हार्ड डिस्क आदि को कुचल (crushed) दिया जाएगा और फिर ई-कचरे के निपटान के लिए राज्य के मौजूदा मानदंडों के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा। डेटा की न तो प्रतिलिपि बनाई जाएगी और न ही उपकरणों को निपटान करते समय उन्हें फॉर्मेट किया जाएगा यानी उपकरण अपनी सामग्री के साथ ही होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव रिकॉर्ड का निपटान करते समय कोई लीकेज और डेटा चोरी न हो। चुनाव रिकॉर्ड का निपटान एक जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाना है कि उक्त निपटान की कार्यवाही पूर्व की भांति जिला स्तर पर ही की जाएगी।

उपरोक्त दिशा निर्देशों से आपके जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों को अवगत कराते हुये पालना सुनिश्चित करवायी जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(नवीन महाजन)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/ 9181 जयपुर, दिनांक 24-9-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा प्रथम - ए, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, रोल्स शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, ईवीएम/वीवीपैट शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, आर.टी.आई. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उपविधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 4/2024/SDR/Vol. II

Dated: 6th September, 2024

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Sub: - Custody, retention, inspection, supply and disposal of election records relating to general/bye election to the House of the People and State Legislative Assembly-regarding

Ref:

- | | |
|---|------------------|
| 1. No. 4/2008/SDR | dated 29.01.2009 |
| 2. No. 3/ER/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2016 | dated 07.09.2016 |
| 3. No. 464/INST/2022/EPS | dated 19.06.2023 |
| 4. No. 464/Counting Arrangements/2023-EPS | dated 18.07.2023 |
| 5. No. 464/Strong room /2023-EPS | dated 18.07.2023 |
| 6. 3/ER/2023/SDR/Vol. V | dated 27.02.2024 |
| 7. 3/ER/2023/SDR/Vol. IV | dated 06.03.2024 |

Madam/Sir,

I am directed to state that Rules 92-94 of the Conduct of Elections Rules, 1961 contain provisions for custody, retention, inspection, supply and disposal of election papers in connection with general/bye election to the House of the People and State Legislative Assembly. Rule 92 deals with the custody of ballot boxes and papers relating to election, Rule 93 deals with the production and inspection of election papers; whereas the provisions for retention and disposal thereof are contained in Rule 94 of the said Rules.

2. In addition to rules mentioned above, the Commission has issued various instructions with regard to custody, storage, inspection, supply, retention and disposal of election papers from time to time. Further, there are instructions of the Commission for recording of various stages of election process through multiple recording devices (e.g. photography, videography, CCTV, webcasting) during the process of nomination, scrutiny, and withdrawal of candidature, allotment of symbols, EVM preparations, campaign activities, polling, counting and declaration of results. These recordings are to be stored in CD/storage devices under safe custody of the District Election Officer as per the extant provisions of the Commission's instructions and the Conduct of Elections Rules, 1961.

3. Under the Rule 92 when an Assembly or Parliamentary Constituency extends over more districts than one, the election papers of that constituency will be kept in the custody of such one of the District Election Officers having jurisdiction over the constituency as the Election Commission may direct. Under this arrangement, normally, the District Election Officer, who is Returning Officer himself/ herself of such multi-district constituency or Returning Officer of such constituency works under his district jurisdiction, will be responsible for the safe custody of these papers. In case of Assembly Constituency spreading over more than one district, the election records shall be kept in the custody of District Election Officer to whom the Returning Officer of that Assembly Constituency reports.

4. Though there are no explicit provisions to deploy electronic recording devices in the electoral process under the electoral laws and the rules made thereunder, however, in order to enhance the transparency measures in the electoral process and inclusivity of different stakeholders during various stages of electoral process, the Commission has introduced different electronic mechanisms to supplement and strengthen the existing law and the rules and such steps are in consonance with the evolving technology and expectations. The statutory provisions governing disclosures are restrictive, however, the records including the electronic contents are provided to different stakeholders liberally through instructional regime. However, the experiences, during the recent time, show that such liberal provisions in the Commission's directions/ instructions have been misused to serve mala fide and ulterior motives by certain non-contestants and to propagate the misconception on electoral processes through smear campaign on social media by selective and out of context use of such liberally provided content. The Commission therefore, in partial modification of the earlier instructions relating to custody, retention, inspection, supply and disposal of election papers and electronic recordings of the above-mentioned events, issues the following comprehensive and composite instructions in this context:

A. Pre Nomination period-

- i) The video recordings, photography and other documents pertaining to the period between announcement and notification of the election shall be kept in the safe custody of the Returning Officer or the District Election Officer, as the case may be till the declaration of result. Thereafter these records shall be sealed and handed over to/ kept by the District Election Officer who shall keep these records in his safe custody as per the provisions of Rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

- ii) After declaration of result, these records shall be retained for a period of three months as per Rule 94(c) of Conduct of Elections Rules, 1961. These records may be disposed-off as per the instructions given under Para 7.
- iii) During the custody of the District Election Officer, the statutory documents shall be opened for inspection and supply thereof, on demand, only to the candidate(s) or elector(s) of that constituency pertaining to that election. The instruction for inspection and supply of election records are given in Para 6.

B. Nomination process-

- i) The election papers and electronic content recorded through photography, CCTV & video recordings shall be kept in the safe custody of the Returning Officer till the declaration of result. Thereafter these records shall be sealed and handed over to the District Election Officer who shall keep these records in his safe custody as per the provisions of Rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.
- ii) After declaration of result, these records shall be retained for a period of one year as per Rule 94(c) of Conduct of Elections Rules, 1961. These records may be disposed-off as per the instructions given under Para 7.
- iii) During the custody of the District Election Officer, the statutory documents shall be opened for inspection and supply thereof, on demand, only to the candidate(s) or elector(s) of that constituency pertaining to that election. The instruction for inspection and supply of election records are given in Para 6.

C. Campaign period-

- i) As regards the documents, video recordings and photography of election campaign activities of candidates and political parties made by the election expenditure monitoring teams, flying squads, SSTs, etc. is concerned, the records shall be kept in the safe custody of the Returning Officer till the declaration of result. Thereafter, these records shall be sealed and handed over to the District Election Officer who shall keep these records in his safe custody as per the provisions of Rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.
- ii) After declaration of result, these records shall be retained for a period of six months as per Rule 94(c) of Conduct of Elections Rules, 1961. These records may be disposed-off as per the instructions given under Para 7.

- iii) During the custody of the District Election Officer, these records shall be opened for inspection and supply thereof, on demand, only to the candidate(s) or elector(s) of that constituency pertaining to that election. The instruction for inspection and supply of election records are given in Para 6.

D. Inside and outside the polling station:

- i) The poll proceedings recorded inside and outside the polling stations in the prescribed Formats, voting machines and event recorded through photography/webcasting/CCTV/videography shall be kept in the safe custody of the Returning Officer or the District Election Officer, as the case may be, till the declaration of result. Thereafter, these records shall be sealed and handed over to/ kept by the District Election Officer as per the provisions of Rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.
- ii) Such records shall be treated as records mentioned in Rule 93(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961 and shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the order of a competent court. However, the webcasting data and videography data/ photography inside the Polling Stations shall be kept in the secured custody of DEO concerned for use during scrutiny process, if required.
- iii) Further, it is clarified that under Rule 49S of the Conduct of Elections Rules, 1961, Presiding Officer is required to furnish a true attested copy of the account of votes recorded as prepared by him in Form 17C Part I only and no other documents, to each polling agent present after obtaining a receipt from the said polling agents, only at the close of poll.
- iv) After declaration of result, these records shall be retained for a period of one year as per Rule 94(b) of Conduct of Elections Rules, 1961. These records may be disposed-off as per the instructions given under Para 7.
- v) On the order of the competent court, if copy (ies) of such data/record are to be provided to the candidate(s) or elector(s) of that constituency, the same may be provided as per norms given in Para 6.

E. Counting and declaration of result:

- i) After the counting process is over, the proceedings of counting and declaration of result recorded through videography/photography/CCTV duly sealed by the

Returning Officer shall be kept in the safe custody of the DEO as per the provisions of Rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

- ii) Such records are part of records mentioned in Rule 93(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961 and shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the order of a competent court.
- iii) After declaration of result, these records shall be retained for a period of one year as per Rule 94(b) of Conduct of Elections Rules, 1961. These records may be disposed-off as per the instructions given under Para 7.
- iv) On the order of the competent court, if copy (ies) of such data/record are to be provided to the candidate(s) or elector(s) of that constituency, the same may be provided as per norms given in Para 6.
- v) However, as per the provision of Rule 93(3) of the Conduct of Elections Rules, 1961, copies of the returns by the Returning Officer forwarded under Rule 64 e.g. return of election in Form 21-E, Form 21C or Form 21D and result sheet in Form 20 may be furnished on a payment of a fee of two rupees for each copy.
- vi) Further, Form 17C Part II is result of counting and is prepared at the time of counting. It is signed by the counting supervisor and also by the candidates or their election/counting agents. A copy of the Form 17 C part II is furnished to the election/counting agent at the time of counting.

F. EVM preparations:

- i) The proceedings recorded in the prescribed Formats and through photography/CCTV/videography during EVM & VVPAT preparations viz. FLC, randomizations, commissioning, dispersal, storage and other activities till the period of filing of Election Petition, in warehouses or strong rooms at different stages of preparations shall be kept in the safe custody of the Returning Officer till the declaration of result. Thereafter, these records shall be sealed and handed over to the District Election Officer who shall keep these records in his safe custody as per the provisions of Rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.
- ii) Such records are part of records mentioned in sub-Rule (1) & (1A) of Rule 93 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority

except under the order of a competent court. However, video recordings, if any related to impart of training and awareness drive shall be kept by the DEO separately and should not be mixed with the mandatory recordings mentioned above.

- iii) After declaration of result, these records shall be retained for a period of one year as per Rule 94(b) of Conduct of Elections Rules, 1961. These records may be disposed-off as per the instructions given under Para 7.
- iv) On the order of the competent court, if copy (ies) of such data/record are to be provided to the candidate(s) or elector(s) of that constituency, the same may be provided as per norms given in Para 6.

G. Other Records:

- i) All records of account of election expenses of a candidate who has lodged it within time and manner shall be retained for a period of one year or till the pendency of case before the Commission.
- ii) All records relating to the account of election expenses of a candidate who has been disqualified u/s 10A of the R. P. Act, 1951 shall be retained for a period of three years from the date on which the Commission's decision under sub-rule (8) of rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, is notified. If the disqualification has been removed by the Commission under Section 11 of the said Act, the records shall be destroyed on the expiry of one year after such removal.
- iii) List of challenged votes (Form 14), receipt book used for collection of challenge fee, shall be retained till one year or till they are audited and audit objections if any, settled whichever is later.
- iv) Dispatch register of postal ballot papers, Register of security deposits, Orders of appointment of Presiding officer or polling officer shall be retained till six months after declaration of results.
- v) During the custody of the District Election Officer, these records shall be opened for inspection and supply thereof, on demand, only to the candidate(s) or elector(s) of that constituency pertaining to that election. The instruction for inspection and supply of election records are given in Para 6.
- vi) These records shall be disposed of after expiry of the period of retention as mentioned above with prior approval of the CEO.

5. There are records other than the records pertaining to preparation and updation of electoral rolls generated during non-election period, which pertain to general electoral management during pre-election period. Such records may be required for internal consumption like reference, internal audit and stock taking etc. and shall be under the supervision of the District Election Officer. Access to these records shall be restricted to official purpose only and shall not be available to any other person. These records shall be destroyed after 30 days of completion of that cycle or as decided by the District Election Officer whichever is later.

6. Inspection and supply of election papers and electronic contents given in Para A to G and fee thereof

- (i) Subject to the provisions of Rule 93 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and the Commission's instructions mentioned herein above, inspection and supply of eligible election documents shall only be provided after completion of 45 days from the declaration of result of the election.
- (ii) If there is any election petition or any other petition is filed or pending before any competent court, then inspection and supply of documents shall be allowed only after order of the competent court.
- (iii) Inspection and supply of copy of any eligible statutory election record shall be allowed only on written application containing the particulars concerning the election record, by the candidate or the elector of the constituency concerned.
- (iv) The application should clearly disclose that the applicant has a direct and tangible interest in such document(s) and the nature of such interest.
- (v) No fee shall be charged when inspection or certified copy of a document is required for official purposes.
- (vi) To avoid removal or damage or mutilation of any election record, effective supervision by officials is necessary and also simultaneous inspection by more than one person along with a companion, if requested so, shall not be allowed.
- (vii) In case of account of election expenses, inspection and supply of copies thereof shall be allowed as per Rule 88 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and Commission's instructions in this regard mentioned at chapter 18 of the Handbook for Returning Officer-2023.

(viii) The procedure to be followed in respect of an application for it shall be the same as for a similar application made in respect of a case dealt with by a Revenue Officer.

(ix) Under Rule 93(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission hereby fixes the following fee for inspection and providing copies of election records, on application by the candidate or elector of the constituency concerned:

Sl.no.	Applicant	Type of Election document/record	Fee for supply of certified copy and timeline	Fee for inspection and timeline
1.	Candidate of the constituency concerned	Any eligible statutory document other than the documents covered under Rule 93(1) of CE Rules 1961. And	Nil. within 30 days of receiving of written application or as per the order of the competent court.	Inspection shall be allowed on the day following the date on which the application is made or on a subsequent day on payment of fee of Rs. 5 per hour of inspection or part thereof.
2.	any elector of the constituency concerned	In case of election records covered under Rule 93(1) of CE Rules 1961 and non-statutory documents/records, order of the competent court is required.	Rs.300/- per CD/storage device (excluding cost of CD/storage device), and @ Rs.2/- per page in case of documents. within 30 days of receiving of written application or as per the order of the competent court.	Inspection on an urgent application shall be allowed on the same day in that case the fees shall be Rs. 10 per hour of inspection or part thereof.

7. Disposal of election papers and electronic contents-

- (i) The disposal of election papers and electronic contents shall be done as per the provisions of Rule 94 of the Conduct of Elections Rules, 1961 read with the above mentioned instructions pertaining to various aspects of elections.
- (ii) Before disposal of these records, the DEO shall ascertain whether any election petition or any other petition is filed or pending before any competent court.

- (iii) If no election petition is filed/pending for the election then the above mentioned election records may be destroyed with the prior approval of the CEO of the State after expiry of abovementioned retention period.
- (iv) Where an election petition or any other petition is pending for adjudication by a court, the records relating thereto should not be destroyed until the expiry of three months has passed from the date of disposal of such petition finally.
- (v) It shall be ensured that advance written intimation shall be given to the contesting candidates and political parties concerned before disposing of the records.
- (vi) Final Result Sheet (Form 20), Declaration of Result of Election (Forms 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 23 and 23A) and Return of Election (Forms 21E and 23B) should be kept as permanent records of election.
- (vii) A table containing various types of records to be destroyed in certain timelines, may be seen at Annexure 'A' and 'B'

8. (a) It is hereby clarified that "competent court" within the meaning of Rule 93(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961 is either any court having jurisdiction to try electoral offences etc. for the prosecution of which the documents mentioned in the said rule are required or the court having jurisdiction to try election petition under Section 80A of the Representation of the People Act, 1951.

(b) If an election petition is pending before the high court and simultaneously the election records are also required to be presented before the court trying an electoral offence matter then in such case the District Election Officer shall seek permission from the high court trying that election petition before the records are supplied to that court on demand/to the petitioner on request.

9. With regard to the electronic recordings recorded through photography/webcasting/CCTV/videography, it shall be ensured that the unedited recordings should be stored in appropriate storage device(s) and be sealed, clearly labelling all the details contained therein including the date, time, time duration, name of the place, constituency and election, immediately after that particular stage of election in the constituency is over. The CD/storage device shall be indexed with a uniform code number in the following standard formulation: State/District/AC/Date of recording/location/Gist of event recorded. It should be ensured that the recordings

of the different processes are duly catalogued and be kept intact and unedited with proper locking seals so that it cannot be copied by anyone after it has been sealed. No guarantee for authenticity and veracity of the contents of the CDs/storage devices will be undertaken under any circumstances and these will be made available on 'as is' basis. While providing the electronic recordings the particulars of the recordings such as election, place, event date & time etc. should be clearly mentioned. The electronic recordings which are the part of the election papers as specified under Rule 93(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961 shall be stored in the trunk in the election paper Strong Room, designated for documents different from EVM/VVPAT strong rooms, where all the statutory documents relating to that election have been stored. The other administrative directions on inspections of records issued vide reference 3rd cited and para 19.8 of Handbook for Returning Officer, 2023 may be ensured.

10. Protocol for safe storage of Polled EVMs, VVPAT, VVPAT slips and election papers:-

All the extant instructions as contained in the latest edition of Manual of EVM and VVPAT and Commission's instruction in the reference 5th cited regarding safe storage of Polled EVMs, VVPAT, VVPAT slips and election papers shall be scrupulously followed.

11. Protocol for opening of election papers strong room for supply of copies/recordings:

A separate log book shall also be maintained and in the event of opening of the strong room, entry should be made about date, time, duration and name(s) of person(s), purpose for opening the strong room. The other protocol for opening strong rooms such as prior intimation to contesting candidates, videography of the activity in the strong rooms, including opening and re-sealing etc. should be scrupulously followed.

12. The election papers and documents shall be shredded centrally in the district or the State as the CEO may decide. The electronic devices containing various electoral data viz. CD, DVD, Pendrive, Hard disk etc. shall be crushed and then disposed off as per the existing norms of the State for disposal of e-waste. The data shall neither be copied nor the devices are formatted while disposing them i.e. the devices shall be

along with their contents. The DEO will ensure that there is no leakage and data theft while disposing off the election records. The election records shall be disposed-off in the supervision of a responsible officer.

- 13.** The above instructions shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,



(S. B. Joshi)
Principal Secretary

ANNEXURE 'A'

Relevant rules of Conduct of Elections Rules, 1961	Type of documents	Retention period after declaration of result of the election. if no petition is pending
Rule 94(a)	Packets of unused ballot papers, Undistributed ballot papers left with RO	6 months
Rule 94(b)	Used ballot paper (whether valid, tendered or rejected), marked copies of electoral roll, declarations by elector, attestation of their signatures, and Register of Voters (Form 17 A). Packet of paper slips of printer under Rule 57 C , counterfoils of used ballot papers	One year Shall not be destroyed except with the previous approval of the Election Commission. [proviso to rule 94(b)]
Rule 94 (c) Subject to any direction to the contrary given by the Commission or by a competent court or Tribunal-	Papers specified in Annexure 'B'	Six months
-do-	List of challenged votes (form 14), receipt book used for collection of challenge fee, dispatch register of postal ballot papers, forms of nomination papers	One years or till they are audited and audit objections if any, settled whichever is later
-do-	Orders of appointment of Presiding officer or polling officer	Six months
-do-	Register of deposits	Six months
-do-	All records of account of election expenses of a candidate who has lodged it	One year

	within time and manner	
-do-	All records relating to the account of election expenses of a candidate who has been disqualified u/s 10A of the R. P. Act, 1951 If the disqualification has been removed by the Commission under Section 11 of the said Act, the records shall be destroyed	Retained for a period of 3 years from the date on which the Commission's decision under sub-rule (8) of rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, is notified. One year after such removal.

List of the papers for destruction - six months after the declaration of result of election

- (1) Form of Notice (Form 1).
- (2) Notice of nominations (Form 3A).
- (3) List of validly nominated candidates under rule 8 (Form 4).
- (4) Form of Notice of withdrawal (Form 5).
- (5) Notice of withdrawal of Candidates (Form 6).
- (6) List of contesting candidates (Form 7A).
- (7) Appointment of election agents (Form 8).
- (8) List of tendered votes (Form 15).
- (9) Appointment of polling and counting agents (Form 10 and 18).
- (10) Office copies of Form 18.
- (11) Revocation of the appointment of election agents, polling agents and counting agents (Form 9, 11, 19).
- (12) Used electoral rolls at a polling station other than the marked copy [Rule 31(3)/49C (3)].
- (13) Record kept by the Presiding Officers regarding voting by blind and infirm electors (Form 14A).
- (14) Packet containing cancelled ballot papers [Rules 39(7) and 41.]
- (15) Notes and records maintained by the Presiding Officer, the declarations made by the polling agents and any other paper directed by the Returning Officer to be kept in a sealed packet.
- (16) List containing names of persons under preventive detention (Rule 21).
- (17) List of electors permitted to vote by postal ballot.
- (18) Applications made by persons subjected to preventive detention for permission to vote by postal ballot received by the Returning Officers.
- (19) Applications for postal ballot papers by electors employed on election duty (Form 12 and Form 12A).
- (20) Postal ballot papers returned undelivered.
- (21) Applications made for reissuing of postal ballot papers.
- (22) Applications for the recount of votes (Rule 63).
- (23) Unused postal ballot papers with counterfoils.

- (24) Notice of counting of votes-time, place and date, etc.
- (25) Notice of inspection of accounts of election expenses.
- (26) Correspondence between the Returning Officer and the candidates and the election or counting agents.
- (27) Application for allotment of symbols.
- (28) Damaged paper seals and unused paper seals including those received back from the Presiding Officers by the Returning Officers.
- (29) General reports, diaries and memo, note-books from the Presiding Officers.
- (30) Notices under clauses (a) and (b) of sub-rule (i) of rule 31/49C
- (31) Packets containing objections by candidates and agents etc., in the course of poll and counting of votes.
- (32) A Sealed packet containing the proceedings drawn by the Returning Officer after counting of votes.
- (33) Sealed packets containing check memos for counting of votes.
- (34) Paper seal account.
- (35) Publicity material such as wall posters, handbills and open statements issued by the candidates at the election.
- (36) Election duty certificates (Form 12-B)
- (37) Declarations under rule 40 (1)/ 49N of Conduct of Elections Rules, 1961